खंड -5 अंक 7 फरवरी -2023

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषयसूची

- "बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे के अध्ययन" पर प्रस्तुति

- तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) की 30वीं बैठक
- "दक्षिण एशिया में निर्मित जल भंडारण" विषय पर कार्यशाला
- डीआरआईपी चरण II और एनडीएसए से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए 9वीं बैठक

- के.ज.आ अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं/साइटों का दौरा/ निरीक्षण
- अनुभागीय समिति की 19वीं बैठक
- त्वरित जोखिम मूल्यांकन ढांचे पर प्रशिक्षण

- जोशीमठ, चमोली जिला, उत्तराखंड के आसपास जमीन धंसने पर राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के संबंध में बैठक
- प्रारूप मॉडल विधेयक "राज्य एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन-2023" पर प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक

- के.ज.आ के अध्यक्ष द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक
- "जलाशयों के मुक्त जलग्रहण क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव की क्षमता का आकलन" पर कार्यशाला

- टीएसी-बीबी की 18वीं बैठक के लिए गुवाहाटी का दौरा और "ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा" योजना का दौरा

- एमसीओ, नागपुर, के.ज.आ द्वारा निगरानी की जा रही परियोजनाएँ
- 31.01.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

- जल क्षेत्र समाचार
- जनवरी-2023 तक एनएचपी की प्रगति/नोट

- जलाशय निगरानी
- डेटा कॉर्नर- जल क्षेत्र के प्रमुख हितधारक

- इतिहास- सारदा से अधिक सिंचाई और बिजली

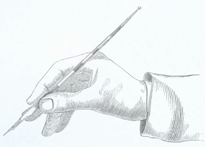

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

"दक्षिण एशिया में निर्मित जल भंडारण" परियोजना पर 30.01.2023 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (डीओएस) द्वारा किया गया था। इस परियोजना को जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्लूएमआई) और वैश्विक जल साझेदारी (जीडब्ल्यूपी) के दक्षिण एशिया कार्यालय द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्र में 3 साल की अवधि के लिए लागू करने का प्रस्ताव है। के.ज.आ, भारत में परियोजना कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकारी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। हमने क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सीडब्ल्यूसी के युवा अधिकारियों के एक समूह को परियोजना में शामिल किया है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) में काठी (सैडल) मृदा बांध, एक स्पिलवे, सिंचाई सुरंग, नेविगेशन सुरंग और चैनल और दोनों किनारों पर दो मुख्य नहरों के साथ एक मृदा सह प्रस्तरपूर (रॉकफिल) (ईसीआरएफ) बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिससे 4.36 लाख हेक्टेयर की अधिकतम सिंचाई क्षमता पैदा की जा सके और साथ ही 960 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन भी किया जा सके व 540 गांवों को पेयजल आपूर्ति तथा 84.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी (नुकसान सहित) को कृष्णा बेसिन में मोड़ा जा सके।2007 के ओएस 04 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2022 के अनुसरण में पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के तकनीकी मुद्दों और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए), केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया। सीडब्ल्यूसी, परियोजना के विभिन्न पहलुओं में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है और बाढ़ के कारण परियोजना में आने वाली समस्याओं के लिए डिजाइन में संशोधन कर समाधान दे रहा हैं।

जल जीवन मिशन को बढ़ावा देते हुए, देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है क्योंकि जल जीवन मिशन के हर घर जल अभियान के तहत देश के 11 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी के नल कनेक्शन से जोड़ा गया है। भारत के तेईस जिलों और 1.53 लाख से अधिक गांवों में 'हर घर जल' है, यानी हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध है। 2019 में मिशन के लॉन्च के समय, 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (16.72%) के पास नल का पानी था। अब तक, जीवन बदलने वाले मिशन के लगभग तीन वर्षों की छोटी अवधि के भीतर, 11 करोड़ (56.84%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो गई है।

"बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे के अध्ययन" पर प्रस्तुति

जैसा कि सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने कहा, 24.01.2023 को "बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे के अध्ययन" पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें अध्यक्ष, के.ज.आ ने रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। प्रस्तुति के दौरान जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और के.ज.आ के अध्यक्ष, मुख्य अभियंता (एचएसओ) और निदेशक, जल विज्ञान (सी) के साथ उपस्थित थे। सलाहकार ने अध्ययन में विचार की गई विभिन्न सिमुलेशन स्थितियों के परिणाम प्रस्तुत किए।

तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) की 30वीं बैठक

तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) की 30वीं बैठक, पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना (1200MW), भूटान के एजेंडे पर "परियोजना कॉलोनी, राष्ट्रीय राजमार्ग और पहाड़ी के लिए सुरक्षा/ स्थिरता की स्थिति और स्थिरता उपायों की आवश्यकता" पर 23.01.2023 को सेवा भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता टीसीसी के अध्यक्ष और सदस्य (हाइड्रो), सीईए श्री एम. ए. के. पी. सिंह और टीसीसी के सह-अध्यक्ष और सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ श्री नवीन कुमार ने की। आरजीओबी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (डीजीपीसी) के एमडी दाशो छेवांग रिनज़िन ने किया। भूटान की शाही सरकार (आरजीओबी), जलविद्युत और विद्युत प्रणाली विभाग (डीएचपीएस), पीएचपीए-I, सीईए, के.ज.आ और डब्ल्यूएपीसीओएस के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया।

निदेशक सीएमडीडी (ईएंडएनई) ने चर्चा में भाग लिया।

"दक्षिण एशिया में निर्मित जल भंडारण" विषय पर कार्यशाला

के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा ने 30.01.2023 को आयोजित "दक्षिण एशिया में निर्मित जल भंडारण" परियोजना की उद्घाटन कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दिया।

इस कार्यशाला का आयोजन क्षेत्र में जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्लूएमआई) और वैश्विक जल साझेदारी (जीडब्ल्यूपी) दक्षिण एशिया के सहयोग से संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग द्वारा किया गया था। कार्यशाला में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पारिस्थितिकी तंत्र व्यवहार्यता के लिए जल भंडारण (प्राकृतिक और निर्मित भंडारण दोनों) के महत्व को रेखांकित किया गया। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूलित करने और कम करने के लिए भविष्य में अधिक निर्मित भंडारण आवश्यक होगा।

के.ज.आ भारत में परियोजना कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकारी संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।

उद्घाटन कार्यशाला के.ज.आ , आईडब्ल्यूएमआई और जीडब्ल्यूपी द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना को पेश करने, भारत में जल भंडारण के मुद्दों पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और परियोजना कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

अपने उद्घाटन भाषण में, श्री वोहरा ने देश में भंडारण के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसने खाद्य आत्मनिर्भरता, ऊर्जा आवश्यकता, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को प्राप्त करने में काफीमदद की है। हालाँकि, भारत में 5745 बड़े बांधों की संयुक्त भंडारण क्षमता केवल 258 बीसीएम(लगभग 200m3/वर्ष/व्यक्ति) है

जो समान जलवायु परिस्थितियों वाले अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार, स्थानीय और क्षेत्रीय जल संकटों के लिए प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में प्रति व्यक्ति जल भंडारण में गिरावट की पहचान करते हुए, उन्होंने भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए जलवायु अनुकूल जल बुनियादी ढांचे और सभी हितधारकों को सहयोग करने और समन्वित तरीके से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री एन.एन. राय, निदेशक, जल विज्ञान (उत्तर) निदेशालय, श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, जल विज्ञान (एन) निदेशालय और श्रीमती पायल गोयल, उप निदेशक, जल विज्ञान (उत्तर) निदेशालय ने उद्घाटन कार्यशाला में भाग लिया।

डीआरआईपी चरण II और एनडीएसए से संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए 9वीं बैठक

19 दिसंबर, 2022 की बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 25 जनवरी, 2023 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ड्रिप-II योजना और एनडीएसए से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मंत्रालय, के.ज.आ और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया।

के.ज.आ अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं/साइटों का दौरा/निरीक्षण

त्लावंग और तुईचांग एचईपी मिजोरम

सीएमडीडी (ई एंड एनई), एचसीडी (ई एंड एनई), तटबंध (ई एंड एनई) के.ज.आ नई दिल्ली के अधिकारियों के साथ-साथ एनईआईडी-II, के.ज.आ , आइजोल के अधिकारियों का त्लावंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मिजोरम और तुइचांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मिजोरम के परियोजना स्थल का संयुक्त दौरा 3 से 8 जनवरी 2023 तक किया गया था।

एनईआईडी-II, के.ज.आ , आइजोल को मंत्रालय की आईडब्ल्यूआरडी योजना के तहत त्लांग एचईपी (120 मेगावाट) परियोजना, मिजोरम का एस एंड आई और डीपीआर तैयार करने का काम सौंपा गया है। डिज़ाइन निदेशालय (ई एंड एनई) यूनिट, के.ज.आ को डीपीआर के लिए डिज़ाइन अध्याय और चित्र तैयार करने का काम सौंपा गया है।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना

17.01.2023 को के.ज.आ में यूजेवीएनएल और के.ज.आ के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड के विभिन्न डिजाइन मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें बांध का गतिशील विश्लेषण, एनआईआरएम द्वारा विभिन्न गुहाओं के संख्यात्मक विश्लेषण की स्थिति, एनर्जी डिसिपेटर व्यवस्था का भौतिक मॉडलिंग, डायवर्जन संरेखण और अन्य मुद्दे शामिल थे।

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना में उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 300 मेगावाट (3X100 मेगावाट) है।

project is 300 MW (3X100 MW).

कनहर सिंचाई परियोजना

श्री सतीश कंबोज, निदेशक, गेट्स डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) डीटीई ने परियोजना अधिकारियों के साथ हाइड्रोमैकेनिकल उपकरणों के चल रहे निर्माण और निर्माण कार्यों के लिए सुझाव देने के लिए 05.01.2023 से 07.01.2023 के दौरान कनहर सिंचाई परियोजना का दौरा किया। कनहर सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की दुधी तहसील में सुगवां गांव के पास कनहर के साथ पगन नदी के संगम के नीचे की ओर स्थित है।

ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना (11200 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश

एनएचपीसी के अधिकारियों के साथ के.ज.आ , सीएसएमआरएस और जीएसआई के अधिकारियों द्वारा ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी), अरुणाचल प्रदेश के परियोजना स्थल का संयुक्त दौरा 16 से 20 जनवरी 2023 तक किया गया था।

एनएचपीसी लिमिटेड को सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम सौंपा गया है। तीन वैकल्पिक बांध स्थल (पारोंग, डिट्टे-डिम्मे और उगेंग) स्थानों के साथ एक पीएफआर के.ज.आ में जांच के अधीन है।

अनुभागीय समिति की 19वीं बैठक

बीसीडी (ई एंड एनई) के निदेशक और उप निदेशक बाढ़ प्रबंधन, कटाव प्रबंधन और डायवर्जन कार्यों से संबंधित डब्ल्यूआरडी 22 की अनुभागीय समिति के सदस्य हैं। अनुभागीय समिति बाढ़ प्रबंधन, कटाव प्रबंधन और डायवर्जनवर्क्स डब्ल्यूआरडी 22 की 19वीं बैठक में श्री सरबजीत कुमार सिंह, उप निदेशक बीसीडी (ई एंड एनई) ने भाग लिया, जो 18.01.2023 को आयोजित की गई थी।

त्वरित जोखिम मूल्यांकन ढांचे पर प्रशिक्षण

विश्व बैंक द्वारा 11 से 13 जनवरी 2023 तक वर्चुअल मोड में बांधों के त्वरित जोखिम मूल्यांकन पर तीन (3) दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में के.ज.आ और डीआरआईपी-2 की कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

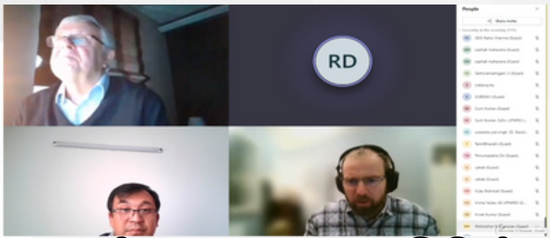

जोशीमठ, चमोली जिला, उत्तराखंड के आसपास जमीन धंसने पर राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के संबंध में बैठक

श्री नवीन कुमार, सदस्य (डी एंड आर), श्री मनोज तिवारी, मुख्य अभियंता (एचएसओ), श्री एन.एन. राय, निदेशक, जल विज्ञान (एस) डीटीई और श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, जल विज्ञान (एन) डी ने 10.01.2023 को जोशीमठ शहर के आसपास प्रभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ, की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया।

प्रारूप मॉडल विधेयक "राज्य एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन-2023" पर प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक

दिनांक 30.01.2023 को प्रारूप मॉडल विधेयक "राज्य एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन-2023" की प्रगति की समीक्षा हेतु सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। श्री पी.एम. स्कॉट, सदस्य (डब्ल्यूपी&पी) और श्री ऋषि श्रीवास्तव, सीई (बीपीएमओ) ने बैठक में भाग लिया। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, सीजीडब्ल्यूबी, एनडब्ल्यूएम आदि के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में, सलाहकार (विधि केंद्र फॉर लीगल पॉलिसी) द्वारा प्रस्तुत मसौदा विधेयक पर विस्तार से चर्चा की गई और विभिन्न पैराग्राफों में कुछ पाठ सुधारों के अलावा, सलाहकार को जल मूल्य निर्धारण पर संशोधन का भी सुझाव दिया गया और उनसे इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नीति का उल्लेख करने का अनुरोध किया गया।

के.ज.आ के अध्यक्ष द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामय्यापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। इस बहुद्देशीय प्रमुख परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) में काठी (सैडल) मृदा बांध, एक स्पिलवे, सिंचाई सुरंग, नेविगेशन सुरंग और चैनल और दोनों किनारों पर दो मुख्य नहरों के साथ एक मृदा सह प्रस्तरपूर (रॉकफिल) (ईसीआरएफ) बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिससे 4.36 लाख हेक्टेयर की अधिकतम सिंचाई क्षमता पैदा की जा सके और साथ ही 960 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन भी किया जा सके व 540 गांवों को पेयजल आपूर्ति तथा 84.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी (नुकसान सहित) को कृष्णा बेसिन में मोड़ा जा सके।

आरसीसी के अनुसार परियोजना की लागत रु.2013-14 पीएल पर 29027.95 करोड़[प्रथम आरसीई (2010-11) के अनुसार मात्राओं के लिए]। दिसंबर 2022 तक परियोजना की कुल प्रगति (कार्य, एलए और आर एंड आर सहित) 48.11% है। शुरुआत से लेकर दिसंबर 2022 तक परियोजना पर किया गया कुल व्यय रु. तक 20766 करोड़ (एनपी के तहत 16,036 करोड़) है। परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बाद दिसंबर 2022 तक भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को कुल 13226 रुपये की प्रतिपूर्ति की गई।

2007 के ओएस 04 और अन्य संबंधित मामलों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2022 के अनुसरण में, पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुशविंदर वोहरा द्वारा 25.01.2023 को बैठक की गई। बैठक में ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए), केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में ओडिशा और तेलंगाना राज्य के तकनीकी मुद्दों और इन मुद्दों पर आंध्र प्रदेश राज्य के विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में के.ज.आ द्वारा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग को के.ज.आ की एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

"जलाशयों के मुक्त जलग्रहण क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव की क्षमता का आकलन" पर कार्यशाला

19 और 20 जनवरी 2023 को "जलाशय के मुक्त जलग्रहण क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव की क्षमता का आकलन" पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन के.ज.आ के मुख्य अभियंता श्री ए.के.खार्या ने किया। श्री आलोक पॉल कलसी, निदेशक, डब्ल्यूएस एंड आरएस निदेशालय ने मुख्य अतिथि और सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी।

उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र हुआ। पहले दिन के तकनीकी सत्र में अवधारणाओं और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, आवश्यक सॉफ़्टवेयर और आर्क जीआईएस, एसडब्ल्यूएटी, एसएजीए टूल और इसके उपयोग की मूल बातें पर प्रस्तुति शामिल थी। टोजो विकास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (टीवीआईपीएल) की टीम/विशेषज्ञों द्वारा कैचमेंट चित्रण, आईएमडी ग्रिडेड डेटा निष्कर्षण, मृदा डेटा प्रोसेसिंग, एलयूएलसी प्रोसेसिंग, डीईएम की चरण दर चरण प्रक्रिया पर प्रस्तुति दी गई। प्रत्येक प्रस्तुति के बाद प्रतिभागियों के साथ प्रश्नोत्तरी और संवादात्मक चर्चाएँ की गईं।

20 जनवरी को तकनीकी सत्र में हरियाणा के गुरुग्राम में टीवीआईपीएल कार्यालय में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल था। तकनीकी सत्र की शुरुआत सामग्री ब्रीफिंग के साथ हुई, जिसके बाद मिट्टी के कटाव की क्षमता की गणना करने के लिए आवश्यक जलग्रहण क्षेत्र के चित्रण और कारकों (आर, के, एलएस, सी, पी) की गणना पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के प्रतिभागियों में के.ज.आ के अधिकारी शामिल थे।

टीएसी-बीबी की 18वीं बैठक के लिए गुवाहाटी का दौरा और "ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा" योजना का दौरा

सदस्य (आरएम), के.ज.आ ने 09 से 12 जनवरी 2023 के दौरान तकनीकी सलाहकार समिति-ब्रह्मपुत्र बोर्ड (टीएसी-बीबी) की 18वीं यात्रा का नेतृत्व किया और "ब्रह्मपुत्र नदी के माजुली द्वीप की बाढ़ और कटाव से सुरक्षा" योजना से संबन्धित कटाव संभावित स्थानों के साथ-साथ नए कटाव वाले स्थानों का दौरा किया और दौरा किए गए स्थानों पर आरसीसी के अनुसार स्पर्स के पोर्कुपाइन/रिकूपमेंट के उपाय सुझाए।

एमसीओ, नागपुर, के.ज.आ द्वारा निगरानी की जा रही परियोजनाएँ

गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना

नहरों को पूर्ण डिजाइन क्षमता तक चलाने से पहले प्रत्यक्ष, ऑन-साइट मूल्यांकन करने और आगे की कार्रवाई विकसित करने के लिए मुख्य अभियंता डी.के.तिवारी के नेतृत्व में के.ज.आ की एक टीम जिसमें निदेशक मनोज मीना और हरीश उमरजे, उपनिदेशक अश्वनी वर्मा और करण रघुवंशी शामिल थे, ने 30.01.2023 को दायीं तट नहरों पर महत्वपूर्ण पैच (ढलान, बैंक आदि की विफलताओं का सामना करना पड़ा) का दौरा किया। यात्रा के दौरान गोसीखुर्द परियोजना, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार और आईआईटी गांधीनगर के अधिकारी उपस्थित थे।

सत्रपोत्रा भंडारण टैंक, एक सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजना

सत्रपोत्रा भंडारण टैंक, एक सतही लघु सिंचाई एसएमआई परियोजना है जिसे वर्ष 2017-18 में विदर्भ और मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के अन्य लंबे समय से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया था और परियोजना को पूरा करने की सुविधा के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में बीड जिले के बीड तालुका के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करना है।

इस परियोजना में 1170 मीटर लंबे और 13.30 मीटर ऊंचे मृदा बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें अनगेटेड स्पिलवे (117 मीटर) भी शामिल है। टैंक का सकल भंडारण 5.74 एमसीएम है।

परियोजना को 14.30 करोड़ रुपये की कार्य लागत और 790 हेक्टेयर अंतिम सिंचाई क्षमता (यूआईपी) के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया था। परियोजना की तीसरी संशोधित अनुमानित लागत 49.44 करोड़ रुपये है। अब तक, परियोजना ने 790 हेक्टेयर की पूर्ण सिंचाई क्षमता पैदा की है और विशेष पैकेज के तहत 46.35 करोड़ रुपये का व्यय किया है। परियोजना को 4.67 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी प्राप्त हुई है।

इस परियोजना की निगरानी नागपुर में के.ज.आ के क्षेत्रीय संगठन के तहत मूल्यांकन निदेशालय, नागपुर द्वारा की जा रही है। श्री डी.गणेश कुमार, उप निदेशक ने परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए 10.01.2023 को परियोजना का दौरा किया।

बोर्सुरी भंडारण टैंक परियोजना, एक सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजना

बोर्सुरी भंडारण टैंक, एक सतही लघु सिंचाई एसएमआई परियोजना है जिसे वर्ष 2017-18 में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया था, ताकि परियोजना को शीघ्र पूरा करने की सुविधा मिले और राज्य संसाधनों के पूरक के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में लातूर जिले के निलंगा तालुका के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करना है।

इस परियोजना में 960 मीटर लंबे और 14.58 मीटर ऊंचे मृदा बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें अनगेटेड लेब्रिंथ प्रकार का स्पिलवे (180 मीटर) भी शामिल है। टैंक का सकल भंडारण 2.347 एमसीएम है।

बोर्सुरी स्टोरेज टैंक परियोजना को वर्ष 2017-18 में 43.25 करोड़ रुपये की लागत वाले विशेष पैकेज में शामिल किया गया था। और 310 हेक्टेयर परम सिंचाई क्षमता (यूआईपी)। परियोजना की पहली संशोधित अनुमानित लागत 57.87 करोड़ रुपये है।

परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है. हालाँकि, अभी तक कोई आईपी नहीं बनाया गया है। विशेष पैकेज के तहत अब तक 53.12 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। परियोजना को विशेष पैकेज के तहत 10.88 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी प्राप्त हुई है।

इस परियोजना की निगरानी नागपुर में के.ज.आ के क्षेत्रीय संगठन के तहत मूल्यांकन निदेशालय, नागपुर द्वारा की जा रही है। श्री डी. गणेश कुमार, उप निदेशक ने परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए 12.01.2023 को परियोजना का दौरा किया।

वैरागढ़ भंडारण टैंक, एक सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजना

वैरागढ़ भंडारण टैंक, एक सतही लघु सिंचाई एसएमआई परियोजना है जिसे वर्ष 2017-18 में विदर्भ और मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के अन्य लंबे समय से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने हेतु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया था और परियोजना को पूरा करने की सुविधा के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करना है।

इस परियोजना में ओजी टाइप स्पिलवे (293 मीटर) सहित 547 मीटर लंबे और 8.99 मीटर ऊंचे मृदा बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। टैंक का सकल भंडारण 6.73 एमसीएम है।

परियोजना को 32,2987 करोड़ रुपये की कार्य लागत और 848 हेक्टेयर अंतिम सिंचाई क्षमता (यूआईपी) के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत 38.00 करोड़ रुपये है। अब तक, विशेष पैकेज के तहत परियोजना पर 46.35 करोड़ रुपये का व्यय किया है। परियोजना को 6.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी प्राप्त हुई है।

परियोजना की निगरानी नागपुर में के.ज.आ के क्षेत्रीय संगठन के तहत मूल्यांकन निदेशालय, नागपुर द्वारा की जा रही है। श्री डी. गणेश कुमार, उप निदेशक ने हाल ही में परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए 11.01.2023 को परियोजना का दौरा किया।

गुरुवर्य स्वर्गीय लक्ष्मणरावजी इनामदार लिफ्ट सिंचाई योजना

गुरुवर्य स्वर्गीय लक्ष्मणरावजी इनामदार लिफ्ट सिंचाई योजना (जिहे कथापुर लिफ्ट सिंचाई योजना), जिला- महाराष्ट्र में सतारा, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल किया गया है। कथपुर गांव में कृष्णा नदी पर एक बैराज का निर्माण किया गया है। इस योजना में कृष्णा नदी से 3.17 टीएमसी पानी को 209.84 मीटर की ऊंचाई तक उठाने और मौजूदा नेर टैंक में छोड़ने की परिकल्पना की गई है। नेर टैंक से पानी नेर टैंक के डाउनस्ट्रीम में 15 केटी वियर वाली येराला नदी और मौजूदा आंधली बांध में और फिर अंधली बांध के डाउनस्ट्रीम में 17 केटी वियर वाली मान नदी में छोड़ा जाएगा। योजना में तीन और

एलआईएस भी प्रस्तावित हैं जिनके नाम नेर-I, नेर-II और आंधली एलआईएस हैं। मौजूदा नेर और अंधली बांध का उपयोग योजना के लिए संतुलन जलाशयों के रूप में किया जाएगा। योजना का कमांड क्षेत्र 27500 हेक्टेयर स्थायी सूखाग्रस्त क्षेत्र (डीपी एरिया) है। इस योजना से महाराष्ट्र के सतारा जिले के मान और खाटव तालुका के 67 गांवों को लाभ होगा।

₹ 647.69 करोड़ की लागत के शेष कार्यों के लिए परियोजना को मार्च, 2022 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया था। 27500 हेक्टेयर (आईसीए/यूआईपी) के निर्माण और ₹ 247.34 करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ अब तक, इसे ₹6.483 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है और 7900 हेक्टेयर यूआईपी बनाया गया है।

इस परियोजना की निगरानी नागपुर में सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालय के तहत निगरानी और मूल्यांकन निदेशालय, पुणे द्वारा की जा रही है।

कुदाली (मध्यम) सिंचाई परियोजना

कुदाली (मध्यम) सिंचाई परियोजना को वर्ष 2009-10 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी अब, पीएमकेएसवाई) में शामिल किया गया था ताकि परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के सतारा जिले में सिंचाई प्रदान करना है।

इस परियोजना में दो बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कुदाली पर महू बांध और कुदाली नदी की सहायक नदी हटगेघर नाला पर हटगेघर बांध। 04 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं यानी 02 एलआईएस अर्थात महू बांध पर रंजनी और दापावाड़ी और 02 एलआईएस यानी कवाड़ी और विवर हटगेगर बांध पर तथा मुख्य नहर प्रणाली एवं वितरण प्रणाली।

कुदाली सिंचाई परियोजना को 2009-10 में 77.0 करोड़ रुपये की कार्य लागत के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल किया गया था। सीडब्ल्यूसी ने 2019 में पीएमकेएसवाई के तहत 412.20 करोड़ (एआईबीपी के लिए 382.29 करोड़ और कमांड 8480 हेक्टेयर परम सिंचाई क्षमता (यूआईपी) के लिए संशोधित लागत अनुमान को "फास्ट ट्रैक प्रोफार्मा क्लीयरेंस" प्रदान किया। एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट (सीएडीडब्ल्यूएम) के

लिए 29.91करोड़ तथा यूआईपी को भी बढ़ाकर 8523 हेक्टेयर कर दिया गया है।

इस परियोजना ने अब तक 1130 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता पैदा की है और रुपये का व्यय किया है। एआईबीपी के तहत 229.30 करोड़। परियोजना ने अब तक CADWM में कोई प्रगति नहीं की है। परियोजना को रुपये की केंद्रीय सहायता भी मिली है। एआईबीपी के तहत 18.14 करोड़।
इस परियोजना की निगरानी नागपुर में सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय संगठन के तहत निगरानी और मूल्यांकन निदेशालय, पुणे द्वारा की जा रही है।

तेम्भू बृहद लिफ्ट सिंचाई परियोजना

तेम्भू बृहद लिफ्ट सिंचाई परियोजना को वर्ष 2017-18 में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया था। केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष पैकेज परियोजना को शीघ्र पूरा करने की सुविधा के लिए राज्य के संसाधनों को पूरक बनाना। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में सतारा, सांगली और सोलापुर जिलों के कराड, कडेगांव, खानापुर, तासगांव, अटपाडी, कवथे-महांकाल और सांगोला तालुका के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करना है।

इस परियोजना में टेंभू गांव के पास कृष्णा नदी पर 285 मीटर लंबे और 16 मीटर ऊंचे बैराज के निर्माण, टेंभू (स्टेज IA, IB), शिवाजीनगर टैंक (स्टेज II), महुली (स्टेज III ए, III बी), वेजेगांव (चरण IV), भुड़ (चरण V, विसापुर एलआईएस और पुनाडी एलआईएस के पास पंप हाउस परिसरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में लगभग 427.60 किमी लंबी नहरें शामिल हैं। परियोजना के लिए सिंचाई जल की आवश्यकता कृष्णा नदी (अपवाह), कोयना बांध, वांग परियोजना और ताराली बांध परियोजना से प्रस्तावित की गई है।

तेंभू लिफ्ट सिंचाई योजना को 2017-18 में रु.1189.04 करोड़ की कार्य लागत और 101,598 हेक्टेयर परम सिंचाई क्षमता (यूआईपी) के लिए विशेष पैकेज में शामिल किया गया था।

इस परियोजना ने चालू वित्तीय वर्ष में 101,598 हेक्टेयर की पूर्ण सिंचाई क्षमता पैदा की है। अब तक विशेष पैकेज के तहत रुपये

1188.52 करोड़ का व्यय किया है। परियोजना को विशेष पैकेज के तहत रुपये 291.13 करोड़ की केंद्रीय सहायता भी मिली है।

बेम्बला बृहद सिंचाई परियोजना

बेम्बला बृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2006-07 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (अब पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत में शामिल किया गया था ताकि परियोजना को शीघ्र पूरा करने की सुविधा के लिए राज्य संसाधनों के पूरक केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में बाभुलगांव तालुका के लंबे समय से सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करना है।

इस परियोजना में 7650 मीटर लंबे समग्र बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें 7203 मीटर लंबा मिट्टी का हिस्सा है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 19.06 मीटर है और बेम्बला नदी के पार 297 मीटर केंद्र में स्थित स्पिलवे है। द्विज्या आकार के स्पिलवे की संख्या 20 है। 18,929 क्यूमेक्स की अधिकतम डिजाइन बाढ़ को पार करने के लिए प्रत्येक 12 मीटर x 8 मीटर आकार के रेडियल गेट है। इसमें 45455 हेक्टेयर के यूआईपी की सिंचाई के लिए 112.4 किमी लंबी दाहिनी तट नहर है। इसमें अपस्ट्रीम SCADA आधारित दबावयुक्त लिफ्ट सिंचाई योजना भी है। देहानी एलआईएस 6968 हेक्टेयर यूआईपी के कमांड में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा।

बेम्बला को 2007-08 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एआईबीपी में शामिल किया गया था। PMKSY-AIBP के तहत कार्यों की लागत ₹2483.54 करोड़ है और PMKSY-CADWM के तहत ₹259.85 करोड़ है।

इस परियोजना की निगरानी नागपुर में सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय कार्यालय के तहत निगरानी और मूल्यांकन निदेशालय, पुणे द्वारा की जा रही है।

परियोजना ने अब तक 49923 हेक्टेयर (यूआईपी) और 17926 हेक्टेयर (आईसीए) की अंतिम सिंचाई क्षमता बनाई है और पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत क्रमशः ₹2574.84 करोड़ और ₹72.30 करोड़ का व्यय किया गया है। परियोजना को एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत क्रमशः ₹1006.26 करोड़ और ₹18.24 करोड़ की केंद्रीय सहायता भी प्राप्त हुई है।

इस परियोजना की निगरानी नागपुर में सीडब्ल्यूसी के क्षेत्रीय संगठन के तहत निगरानी निदेशालय, नागपुर द्वारा की जा रही है।

31.01.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टतः कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-23	व्यय	व्यय(%में)
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	140.13	129.8588	92.67%
2.	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	11.640	7.2875	62.61%
3.	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	11.3625	7.7441	68.15%
4.	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	8.56	7.867	91.90%
5.	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	31.7086	12.5201	39.48%
6.	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-II	25.00	4.91	19.64%

जल क्षेत्र समाचार

- भारत के जल विजन 2047 का ब्लूप्रिंट तैयार, नदियों पर बांध बनाकर पानी को हथियार बना रहा चीन : पटेल (दैनिक भास्कर, 03.01.2023)
- सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होगा जल संरक्षण, जनभागीदारी जरूरी : मोदी (अमर उजाला, 06.01.2023)
- जोशीमठ में भू–धंसान का अध्ययन करेगी कमेटी (अमर उजाला, 07.01.2023)
- वाटर गवर्नेंस के लिए जरूरी...जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत : गजेंद्र (हरि भूमि, 07.01.2023)
- तलछट जमा होने से भारत के 3,700 बांधों के अस्तित्व को खतरा (जनसत्ता, 10.01.2023)
- 2050 तक देश के 3,700 बांध की जल संग्रह क्षमता 36 फीसदी हो जाएगी कम (अमर उजाला, 10.01.2023)
- केन–बेतवा लिंक प्रोजेक्ट : पन्ना नेशनल पार्क की भूमि के बदले 4208 हेक्टेयर जमीन देगी सरकार (दैनिक भास्कर, 11.01.2023)
- 'जलयुद्ध' की तैयारी कर रहा चीन, भारत ने भी कसी कमर (राजस्थान पत्रिका, 20.01.2023)
- हरियाणा को अगले 3 वर्षों में बाढ़ मुक्त बनाएंगे : सीएम मनोहर लाल (हरि भूमि, 20.01.2023)
- यमुना की सफाई पर एलजी ने ली बैठक, कई दिशा–निर्देश जारी (हरि भूमि, 21.01.2023)
- भारत को बदल देगी नदी जोड़ परियोजना (राजस्थान पत्रिका, 23.01.2023)
- सिंधु जल संधि : आगे की कार्रवाई बातचीत पर निर्भर : जयशंकर (अमर उजाला, 29.01.2023)

जनवरी-2023 तक एनएचपी की प्रगति/नोट

क्र.सं.	वस्तु	वर्तमान स्थिति
1.	नए ध्वनिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर (एडीसीपी) की खरीद	50 एडीसीपी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग की खरीद का ठेका 23-05-2022 को मेसर्स ए एंड एस क्रिएशंस को दिया गया था। 50 एडीसीपी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम पूरा हो चुका है।
2.	वेग राडार	1. 19 वेलोसिटी रडार सिस्टम की खरीद का अनुबंध मैसर्स पैन इंडिया कंसल्टेंट प्रा लिमिटेड को दिया गया है।19 में से 06 वीएसआर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग पूरी हो चुकी है। 2. 13 वेलोसिटी रडार सिस्टम की खरीद का अनुबंध मैसर्स पैन इंडिया कंसल्टेंट प्रा लिमिटेड को दिया गया है। 13 में से 11 वीएसआर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग पूरी हो चुकी है।
3.	हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग कर जलाशय अवसादन अध्ययन	चरण- I (32 जलाशयों) के लिए कार्य जनवरी, 2021 में प्रदान किया गया है।32 में से 22 जलाशयों के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है और शेष प्रक्रियाधीन हैं। चरण- II (87 जलाशयों) के लिए काम जनवरी, 2023 में सौंपा गया था और अनुबंध 09.02.2023 को हस्ताक्षरित किया गया था।
4.	गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान सहित प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली	रुपये 11.40 करोड़ का अनुबंध दिया गया (कार्य 11 अगस्त, 2021 से शुरू हुआ)। दूसरा प्रदेय पूरा हो चुका है और तीसरा और चौथा प्रदेय प्रस्तुत किया जा चुका है और समीक्षाधीन है।
5.	विस्तारित जलविज्ञान पूर्वानुमान (ईएचपी) का परामर्शी कार्य	25.17 करोड़ रुपये का अनुबंध प्रदान किया गया (जुलाई 2020 से काम शुरू हुआ)। पहला (स्थापना रिपोर्ट), दूसरा (इनपुट आंकड़े विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करना और अनुमोदन), और तीसरा (कम प्रवाह के मौसम, उच्च प्रवाह के मौसम व परीक्षण के लिए मॉडल विकास) वितरण पूरा हो चुका है। चौथा वितरण प्रस्तुत कर दिया गया है और समीक्षाधीन है।
6.	बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन	अध्ययन पूरा हो चुका है
7.	नर्मदा बेसिन में वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली	अनुबंध प्रदान किया गया- 7.07 करोड़ रुपये (कार्य सितंबर, 2020 से शुरू हुआ)। सभी 48 साइटें पूरी हो चुकी हैं (स्थापित) और अंशांकन प्रक्रिया में है।
8.	अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण प्रणाली	अनुबंध प्रदान किया गया- 8.12 करोड़ रुपये (काम 06 नवंबर, 2020 से शुरू हुआ)। 33 साइटों पर टेलीमेट्री उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन का काम पूरा हो चुका है। शेष प्रक्रियाधीन हैं।
9.	गंगा बेसिन में एकीकृत जलाशय संचालन	अनुबंध प्रदान किया गया- 6.42 रुपये (कार्य 1 अक्टूबर, 2021 से शुरू हुआ)। सुपुर्दगी 1: आरंभिक रिपोर्ट, पूरी हो चुकी है। प्रदेय डी2, डी3, डी4 और डी5 प्रस्तुत कर दिए गए हैं और समीक्षाधीन हैं।
10.	सात नदी बेसिन में तलछट दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधारित गणितीय मॉडलिंग	विकास चरण पूरा हो गया है. दूसरा चरण शुरू हो चुका है.

जलाशय निगरानी

के.ज.आ साप्ताहिक आधार पर देश के 143 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 18 जलाशय जलविद्युत परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 34.960 बीसीएम है। इन 143 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 177.464 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 68.83% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 25.01.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 115.887 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 65% है। हालांकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल सजीव भंडारण 118.507 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 97.345 बीसीएम था। इस प्रकार, दिनांक 25.01.2023 के

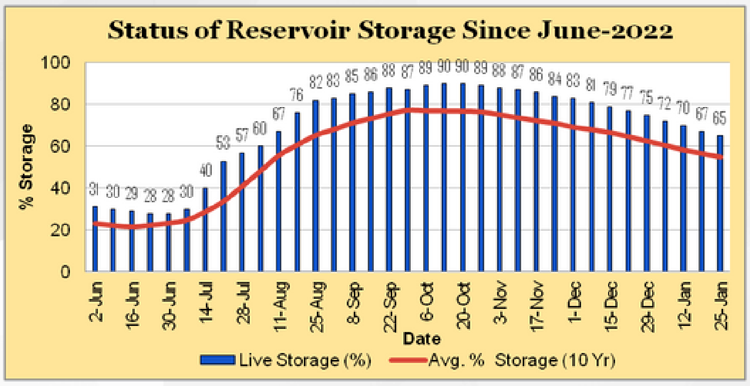

बुलेटिन के अनुसार 143 जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सजीव भंडारण का 98% प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत सजीव भंडारण का 119 प्रतिशत है।

डेटा कॉर्नर- जल क्षेत्र के प्रमुख हितधारक

जल शक्ति मंत्रालय

केंद्र सरकार संगठन

संलग्न कार्यालय

1. केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.)
2. केन्द्रीय मृदा एवं अनुसंधान शाला (सीएसएमआरएस)

अधीनस्थ कार्यालय

3. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड
4. केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण
5. केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला
6. बनसागर नियंत्रण बोर्ड
7. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
8. फरक्का बैराज परियोजना
9. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड
10. राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र

संलग्न कार्यालय

11. तुंगभद्रा बोर्ड
12. बेतबा नदी बोर्ड
13. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
14. गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड
15. कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

निगमित निकाय

16. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
17. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण

पंजीकृत सोसायटी/स्वायत्त निकाय

18. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
19. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
20. उत्तर पूर्वी क्षेत्र जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान
21. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
22. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
23. पोलवरम परियोजना प्राधिकरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

24. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
25. जल एवं विद्युत परामर्श सेवा लिमिटेड

राज्य सरकार विभाग

- सिंचाई
- बाढ़ नियंत्रण
- जल संसाधन
- जल विभाजन प्रबंधन
- नदी विकास
- जल आपूर्ति
- शहरी स्थानीय निकाय

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

- राष्ट्रीय जल अकादमी (NWA)
- डबल्यू ए एल एम आई (WALMI)
- एनईआरआईडबल्यूएएलएम (NERIWALM)
- डबल्यूएएलएएमटीएआरआई (WALAMTARI)
- सीडब्ल्यूआरडीएम (CWRDM)
- राजीव गांधी भू-जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान शाला

गणतंत्र दिवस

गैलरी

श्री टी.के.शिवराजन, मुख्य अभियंता, सी एंड एसआरओ द्वारा चालियार सब डिवीजन, कोझीकोड के अंतर्गत जीडीएसक्यू साइटों पुलमंथोल और कराथोडु का निरीक्षण।

वैनगंगा नदी पर के.ज.आ स्थल कुम्हारी में पुनर्निर्मित जल गुणवत्ता प्रयोगशाला (स्तर -1) का औपचारिक उद्घाटन 28.01.2023 को श्री धीरेंद्र तिवारी, मुख्य अभियंता, एमसीओ, के.ज.आ, नागपुर द्वारा किया गया।

श्री पंकज कुमार, आईएएस, सचिव (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) ने दिनांक 27.01.2023 को लोअर यमुना डिवीजन, के.ज.आ, आगरा (वाईबीओ) के तहत यमुना नदी पर पोइया घाट, जीडीएसक्यू स्थल का दौरा किया।

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष (के.ज.आ) और भारत सरकार के पदेन सचिव ने हिमाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक की।

श्री कमल कुमार जांगिड़, अधीक्षण अभियंता, आईसी, के.ज.आ, गंगटोक, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने सिक्किम में (12.01.2023 से 15.01.2023 के दौरान) बाढ़ और भूस्खलन के कारण नुकसान के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) में भाग लिया।

इतिहास- सारदा से अधिक सिंचाई और बिजली

सारदा हिमालय क्षेत्र की एक बारहमासी नदी है, जो घाघरा के साथ मिलकर, पहाड़ की बर्फीली ऊंचाइयों में कल्ल नदी के रूप में उभरने वाली महान गंगा को सम्मान देती है, यह भारत-नेपाल सीमा पर नैनीताल जिले में टनकपुर की ओर बहती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, खीरी और सीतापुर जिलों से होते हुए सारदा के रूप में दक्षिण-पूर्व में बहती है और लखनऊ से लगभग 50 मील उत्तर-पूर्व में घाघरा में मिल जाती है।)

अतीत

सारदा की घाटी देश के अधिकांश हिस्सों की तरह मानसून आपूर्ति के समान उतार-चढ़ाव के अधीन है, जिसे कृषि उत्पादन के लिए निरंतर नदी प्रवाह की बड़ी तथा परिवर्तनीय, जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। 1870 से शुरू होकर, 60 वर्षों की अवधि में विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित, चर्चा, संशोधित, परित्यक्त और पुनर्जीवित की गईं। उस पूरे अंतराल में वह क्षेत्र जो नदी से लाभान्वित हो सकता था, बार-बार अकाल और अभाव के दौर से गुजरा। तालुकदारों, जिन्होंने कभी सिंचाई नहरों का विरोध किया था, ने भी माना कि उनकी भूमि की सुरक्षा केवल सुनिश्चित जल आपूर्ति प्रदान करने में ही है। इस प्रकार बनबसा में अब प्रसिद्ध बैराज के साथ उत्तर प्रदेश में सारदा नहर पूरी हुई, जो सारदा नदी के पानी को ऊपर ले जाती है और इसे बड़ी नहर में डालती है। आज नहर लगभग 15,00,000 एकड़ भूमि को सिंचित करती है और इससे बिजली का विकास भी शुरू हो गया है, जिसकी परिकल्पना नहर योजना शुरू होने के समय नहीं की गई थी।

विस्तारित उपयोग

1950 के दशक में, लगभग 30 वर्षों की सिंचाई सेवा के बाद, अधिक सिंचाई और अधिक बिजली के लिए नहर के माध्यम से सारदा नदी से और अधिक जल की आवश्यकता थी। 1956 में स्थापित सारदा पावर हाउस के निर्माण ने पूरे वर्ष बिजली इकाइयों को चलाने के लिए सारदा नदी के पानी के एक हिस्से को मोड़ना अनिवार्य बना दिया है और इस पानी को बिना किसी लाभ के बिना किसी योजना के चैनल में प्रवाहित करना पड़ता है। इसके अलावा, राज्य का सिंचाई विभाग सर्दियों की अवधि में 10,000 क्यूसेक वाली सारदा नहर में जल आपूर्ति की जांच करने के तरीकों की उत्सुकता से खोज कर रहा है, जब नदी का डिस्चार्ज

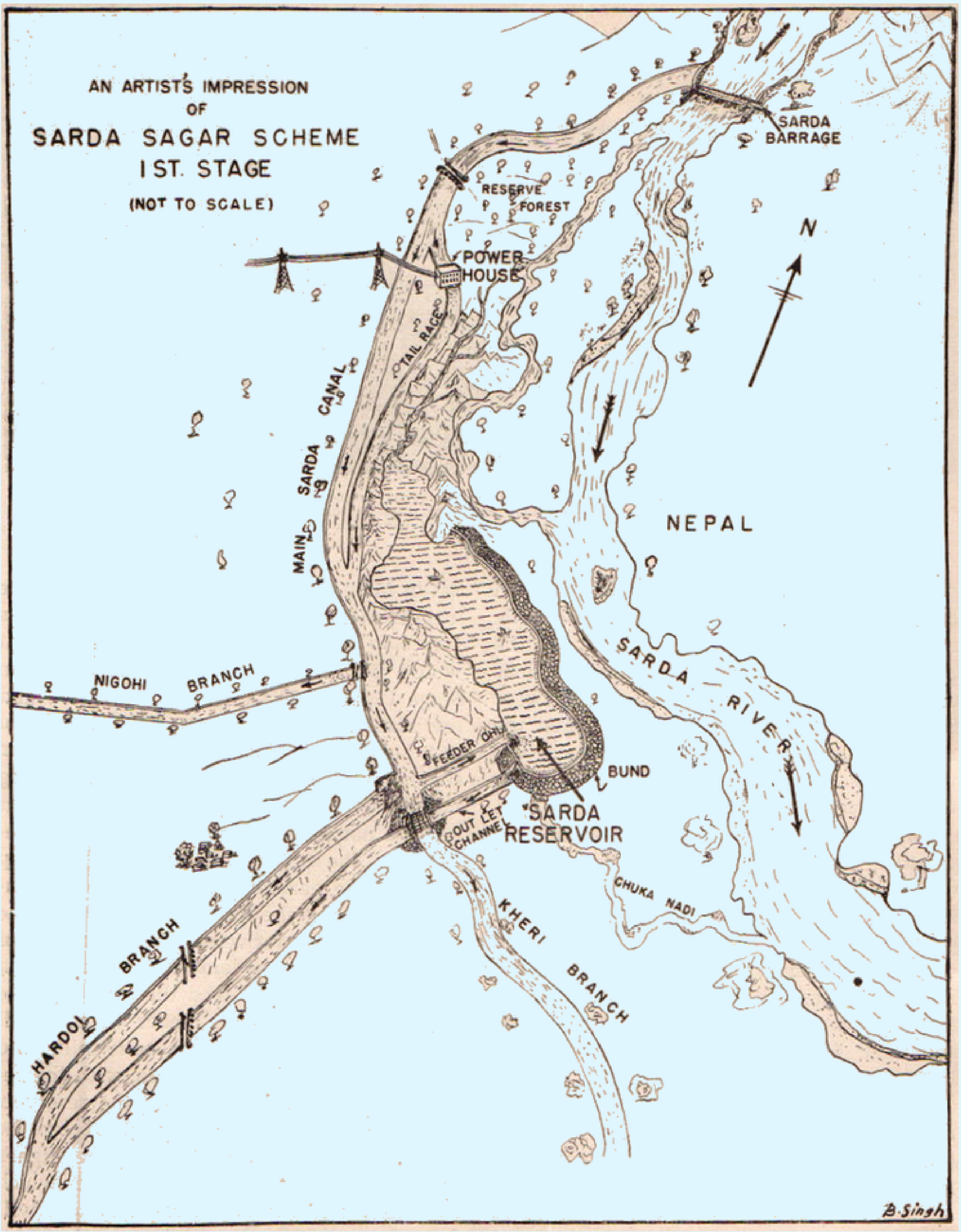

5,000 क्यूसेक से कम हो जाता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पानी की बहुत माँग थी।

हिमालय में कोई भी भंडारण योजना महंगी होगी और साथ ही एक दीर्घकालिक योजना भी होगी। इसलिए नहर के किनारे के मैदानी इलाकों में उपयुक्त स्थल खोजने के प्रयास किए गए। दो भंडारण योजनाओं की जांच की गई, अर्थात् नहर के दाहिने किनारे पर सुरई सागर और माला सागर। इनसे क्रमशः 44 और 78 वर्ग मील जलमग्न हो जाएँगे क्योंकि उनकी क्षमता 465 और 70 लाख एकड़ फीट है। लेकिन दोनों योजनाएं अपने पहले चरण में ही लगभग 16,000 एकड़ अच्छे साल वन को जलमग्न कर देंगी। इसलिए इन साइटों को छोड़ दिया गया था।

अंत में जलाशय के लिए सारदा नहर के बायीं ओर नीचे 25 वर्ग मील का एक क्षेत्र चुना गया, जो सारदा पावर हाउस के विसर्जनी चैनल के पांचवें मील से लेकर सारदा मुख्य नहर के 26वें मील तक उस बिंदु के करीब फैला हुआ था, जहां यह खीरी और हरदोई शाखाओं में विभाजित होता है (मानचित्र भी देखें)। चरण-I में इस जलाशय द्वारा जलमग्न होने वाली 15,500 एकड़ जमीन में से केवल 1,200 एकड़ पर खेती की जाती है और खड़े जंगल 2,400 एकड़ में फैले हुए हैं, बाकी बंजर भूमि है। साइट के अन्य फायदे भी हैं। चूका और सारदा नदी के खादर की ओर खड़ी ऊंची चोटी जलाशय के पश्चिम में एक प्राकृतिक किनारा बनाती है। सारदा और चूका नदियों के बीच के जलक्षेत्र के साथ पूर्वी किनारा 12 मील तक मृदा बांध से बना है। सारदा सागर की सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई है कि चूका इसमें समाहित है और कृत्रिम झील को अपनी सारी जल आपूर्ति प्रदान करता है। एक फीडर चैनल सारदा नहर को जोड़ता है, जहां यह जलाशय के साथ हरदोई और खीरी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यह चैनल सारदा जलग्रहण क्षेत्र द्वारा ऊपरी बैराज तक एकत्र किए गए अतिरिक्त पानी से जलाशय को भरता है। नदी में मानसून अधिशेष जल जो कि सारदा नहर प्रणाली प्रवाह से अधिक है, सारदा नहर और 2,000- क्यूसेक फीडर चैनल से जलाशय में प्रवाहित होता है। बाद में पानी का उपयोग जलाशय से 1,500 क्यूसेक क्षमता के 1.75-मील बहिर्गम चैनल के माध्यम से अनुप्रवाह भूमि की रबी फसल की सिंचाई के लिए किया गया, जो फीडर चैनल के अंतर्गम के करीब से निकलता है, लेकिन निचले स्तर पर। इसी तरह, सर्दियों की बारिश जलाशयों में जमा हो जाती थी और

शुरुआती ख़रीफ़ और गन्ने की फ़सलों के लिए तब तक उपलब्ध रहती थी जब तक कि हिमालय की बर्फ पिघलना शुरू न हो जाए और नदी को पानी न मिल जाए। सारदा सागर योजना की एक और ध्यान देने योग्य विशेषता यह है कि, जैसा कि पहले बताया गया है, पूरे वर्ष विसर्जनी चैनल के माध्यम से सारदा पावर स्टेशन से आने वाला सारा पानी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि भविष्य में उपयोग के लिए सारदा सागर में भेज दिया जाएगा।

फीडर चैनल को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि जलाशय में आने वाली मोटी गाद झील की उपयोगी भंडारण क्षमता को प्रभावित किए बिना झील के एक विशाल खोखले में जमा हो जाती है। सारदा सागर में 2.6 लाख एकड़ फीट पानी है और यह 25 वर्ग मील में फैला हुआ है।

परियोजना की विशेषताएं

संक्षेप में, सारदा परियोजना में जलाशय के लिए 12-मील के मृदा बांध का निर्माण, 2,000 क्यूसेक क्षमता का 2-मील अंतर्गम चैनल, 1.75 मील के लिए 1,500 क्यूसेक क्षमता का निम्न स्तर का बहिर्गम चैनल, लगभग 13.5 मील की समान क्षमता की एक सहायक हार्डोई शाखा और रीमॉडलिंग शामिल है। मुख्य सारदा नहर की क्षमता 9,300 से बढ़ाकर 11,000 क्यूसेक करने, सारदा बैराज गेटों को 2 फीट बढ़ाने और सारदा की रीमॉडलिंग और खीरी शाखाओं की रीमॉडलिंग और कमान क्षेत्र में सारदा सागर की आपूर्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य शामिल हैं।

निर्माण प्रगति

सारदा परियोजना के पहले चरण का काम मार्च 1954 में शुरू हुआ। सारदा बैराज के गेटों को प्रस्तावित ऊंचाई तक बढ़ाया गया और नहर को निर्धारित 11,000 क्यूसेक पानी लेने के लिए फिर से तैयार किया गया। भारत-नेपाल सीमा पर इस अत्यधिक मलेरियाग्रस्त और दलदली तराई जंगल में जलाशय पर लगभग 10,000 मजदूर, 3,000 गधे और 400 तकनीशियन लगे हुए थे। चूँकि इस क्षेत्र में काम केवल नवंबर से मई के अंत तक ही संभव था, इस अवधि के दौरान चौबीसों घंटे काम किया जाता था। मिट्टी खोदने के काम के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई करने वाले उपकरण, डोजर और ट्रकों का उपयोग किया गया है और पंपिंग सेटों ने दिन-रात काम करके नहर के किनारे झरने के पानी को 10 से 15 फीट तक कम कर दिया है, जहां चिनाई का काम किया जाना था और कंक्रीट की नींव रखी गई थी। जून 1957 से अब तक लगभग 220 मिलियन घन फुट मिट्टी का काम, 4.5 लाख घन फुट ईंट की चिनाई और 5 लाख घन फुट सीमेंट कंक्रीट का काम पूरा हो चुका है। विभिन्न विशेषताओं की प्रगति इस प्रकार है:

लाभ

सारदा सागर परियोजना के पहले चरण के पूरा होने से उन्हें **190,000** एकड़ की सिंचाई करने में मदद मिलती है, जिससे प्रति वर्ष

नहरों का पुन:प्रतिरूपण	337 मील
नए चैनल और शाखाओं का निर्माण	534
फीडर चैनल का निर्माण	2
सारदा बहिर्गम चैनल का निर्माण	1.75
अपवाह	15
अनुप्रस्थ अपवाह कार्य	20 इकाई
बांध में मृदाकार्य और सहायक हरदोई शाखा	17.8 करोड़ क्यू. फीट

लगभग 70,000 टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। चीनी और चीनी उत्पादों की उपज लगभग 11,000 टन और मछली उत्पादन लगभग 20,000 टन प्रति वर्ष होने की उम्मीद थी।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 4.8 करोड़ रुपये है, जो 8,000 रुपये प्रति मिलियन घन फीट पानी की दर से उपयोगी भंडारण प्रदान करेगी।

परियोजना के दूसरे चरण में जलाशय के तालाब के स्तर को 12 फीट और बढ़ाने की परिकल्पना की गई है, और इस चरण पर काम किया जाएगा। इस योजना में 19,700 किलोवाट की विद्युत क्षमता की भी पुष्टि की गई है, जिसे जलाशय के बहिर्गम चैनल के नीचे सहायक हरदोई शाखा के साथ विकसित किया गया था।

ये सभी लाभ उत्तर प्रदेश में सारदा सागर के नियंत्रण वाले क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे।

(स्रोत: भागीरथ सितम्बर 1957)

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री सुनिलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in